



भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञापित

28 नवम्बर 2022

पीएलजीए का 22वे वर्षगांठ मनाओ!

देशभर में वर्गसंघर्ष व गुरिल्ला युद्ध को व्यापक व तेज करें!

‘समाधान’ हमले को परास्त करें! जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं!

जनमुक्ति गुरिल्ला सेना (पीएलजीए) का 22वें वर्षगांठ समारोहों को देशभर में ग्रामीण व शहरी इलाकों में क्रांतिकारी उत्साह के साथ जोरशोर से मनाने तमाम पार्टी कतारों, पीएलजीए यूनिटों, क्रांतिकारी जन सरकारों, जन संगठनों व क्रांतिकारी जनता को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी आह्वान करती है। देशभर में जनयुद्ध को जड़ से मिटाने के लिए दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी ‘समाधान’ हमले का मुकाबला करते हुए वर्ग संघर्ष व गुरिल्ला युद्ध को व्यापक व तेज करते हुए जनाधार बढ़ाते हुए, गुरिल्ला सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाने का आह्वान करती है।

तमाम पार्टी कमेटियों, कमांडो, पीएलजीए कमांडरों एवं योद्धाओं, पार्टी सदस्यों, क्रांतिकारी जन सरकारों, जनसंगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं, जन मिलिशिया सदस्यों, क्रांतिकारी जनता, और राजनीतिक, सैनिक, सांगठनिक, टेक्निकल एवं सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सीसी क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। सीसी की विश्वास है कि घायल हुए कामरेडो शीघ्र ठीक होंगे।

पिछले सालभर में अपनी जान कुरबानी किए वीर गुरिल्ला योद्धाओं को सीसी सिर झुकाकर विनम्रता से क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। विगत 11 महीनों में देशभर में 132 कामरेड शहीद हुए।

केंद्र व राज्य सरकारें भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए मई 2017 में 5 वर्ष की समयसीमा रखकर प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक ‘समाधान’ हमले को आरंभ किया। इस हमले को हराने के लक्ष्य से हमारी पार्टी के नेतृत्व में वीर पीएलजीए ने इस पूरे समयकाल में इस युद्ध में जनता व जन मिलिशिया की भागीदारी को अलग कर नहीं देखा जा सकता।

दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 तक बीते 11 महीनों के समय में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए ने देश के विभिन्न गुरिल्ला जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में लगभग 200 गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इनमें दुश्मन के पुलिस, अर्धसैनिक एवं कमांडो बलों के 31 जवानों को उन्मूलन कर, 154 जवानों को घायल किया। उनके पास से सात आधुनिक हथियारों, सैकड़ों कारतूस और अन्य सैन्य साजो सामान को जब्त किया। 69 पुलिस मुखबिरों, सात शोषक राजनेताओं, छः जन-दुश्मनों और छः गद्दारों को उन्मूलन किया। कई जगहों पर सरकारी संपत्ति और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की लूटी संपत्ति को ध्वस्त किया। लगभग 100 मुठभेड़ों में पुलिस, अर्धसैनिक एवं कमांडो बलों का पीएलजीए बलों ने प्रतिरोध किया।

कुल मिलाकर देखा जाए, इन 11 महीनों में प्रतिक्रांतिकारी ‘समाधान’-प्रहार हमले को हराने के लिए हमारे पीएलजीए बल दुश्मन के सशस्त्र बलों पर योजनाबद्ध एम्बुशों, मौकापरस्त एम्बुशों, स्नाईपर कार्रवाइयों, बूबीट्रैप व रिमोट कार्रवाइयों, ध्वस्त कार्रवाइयों, दुश्मन की आपूर्ति जब्ती, पुलिस मुखबिरों का उन्मूलन, प्रतिक्रांतिकारी गद्दारों का उन्मूलन, जन-दुश्मनों का उन्मूलन, पुलिस कैंपों पर इंप्रूवाइज्ड आर्टिलरी से शेल्लिंग किया, स्पाइक होल्स खोदा।

पिछले दो वर्षों से दंडकारण्य और बिहार-झारखंड में पुलिस कैंपों, खदानों, सड़क-पुलिया एवं डेम परियोजनाओं के खिलाफ, पुलिस हत्याकांडों व नरसंहारों के खिलाफ, कुल मिलाकर देखा जाए, साम्राज्यवादी कंपनियों, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी कंपनियों के खिलाफ, उनके स्थानीय दलालों के खिलाफ, केंद्र व राज्य सरकारों के खिलाफ, कार्पोरेटीकरण-सैन्यकरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनांदोलन जारी हैं। इन आंदोलनों में हजारों की संख्या में जनता गोलबंद हो रही है।

देश के आंदोलन के इलाकें समेत अन्य इलाकों में साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देशीय दलाल पूंजीपतियों के कार्पोरेट कंपनियों, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न किस्म के बुनियादी सुविधाओं – सड़क, डेम, पॉवर प्लांट आदि तमाम परियोजनाओं के खिलाफ व्यापक जनांदोलन जारी हैं। कृषि क्षेत्र और जंगलों को कार्पोरेटों को हवाला करने के खिलाफ, आंदोलन के इलाकों को सैन्यकरण करने के खिलाफ

आंदोलन के इलाकों में और बाहर भी जनांदोलन जारी हैं। भीमा कोरेगांव आदि षडयंत्रकारी मामलों में बंदी बनायी गयी राजनीतिक कैदियों की रिहाई करने, 'उपा' आदि फासीवादी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जनांदोलन जारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के जनयुद्ध की अंतरराष्ट्रीय भाईचारा कमेटी (ICSPWI) के नेतृत्व में हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन पर दलाल शासक वर्गों के फासीवादी हमले के खिलाफ, भारत के जनयुद्ध के समर्थन में लगभग 30 देशों में भाईचारा आंदोलन बढ़ रहे हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए, अपेक्षाकृत वर्ग संघर्ष व्यापक एवं तेज हो रहा है। इस दौरान विभिन्न किस्म के संयुक्त मोर्चा के मंच गठित हो रहे हैं। इस क्रम में, क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी बढ़ रही है और मित्र शक्तियों का समर्थन बढ़ रहा है।

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा साढ़े छः लाख से अधिक पुलिस, अर्धसैनिक एवं कमांडो बलों को आंदोलन के इलाकों में तैनात किया। 2020 की शुरुआत से 2021 मार्च तक आंदोलन के इलाकों में सीआरपीएफ ने 23 फार्वर्ड ऑपरेशनल बेसों (FOB) और मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 35 फार्वर्ड ऑपरेशनल बेसों को लगाया। पिछले एक दशक से दुश्मन ने आंदोलन के इलाकों में निगरानी (सरवाईलेंस) के लिए विभिन्न किस्म के ड्रोनों का इस्तेमाल करता आया है। लंपट युवा को लेकर स्व-रोजगार योजनाओं के नाम पर उन्हें मुखबिर बना रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आंकलन किया कि 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि अपेक्षाकृत नहीं होगी, विश्व के अधिकतर देश आर्थिक मंदी से शिकार हो जाएंगे। विश्व की एक तिहाई अर्थव्यवस्था इस वर्ष या अगला वर्ष सिकुड़ जाएगी और विश्व के तीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एवं चीन में गतिरोध की स्थिति (स्टागनेशन) उत्पन्न हो जाएगी। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण नीतियों के अमल के मजदूर वर्ग आंदोलन के रास्ता में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

देश में केंद्र में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी 2047 तक देश को 'हिंदू राष्ट्र' के रूप में बदलने का तीव्र कोशिश में लगे हुये हैं। तमाम क्रांतिकारी-जनवादी शक्तियों, उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं एकताबद्ध होकर संगठित प्रतिरोध आंदोलन एवं जनयुद्ध को जारी रखने की आवश्यकता है। आज भारत की जनता के सामने सबसे पहला, अत्यंत मुख्य, प्रधान और फौरी कर्तव्य यही है।

अगले दिनों में विश्व में एवं देश में जनांदोलनों का उभार समेत विश्वभर में तीसरा दौर का क्रांतिकारी उभार आएगा।

राज्याधिकार के लिये, जनता को जागरूक कर वर्ग संघर्षों एवं गुरिल्ला युद्ध को व्यापक व तेज करना अगुवा दस्ता कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है। 'समाधान' हमले को हराएं! क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अंतिम जीत हमारा ही है।

22वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएलजीए की ऊंचा उठाएं। 'समाधान' हमले का मुकाबला कर बरकरार रहा क्रांतिकारी आंदोलन की अजेयता पर बड़े पैमाने पर प्रचारित-प्रसारित करें।



अभय
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी